

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

हि हिन्दुस्तान

EWSPAPERS

DATED 16-9-2022

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली नगर निगम पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया ट्वीट

कूड़े के नए पहाड़ बनाना चाहता है निगम : आप

आरोपों को साबित करें
उपमुख्यमंत्री : भाजपा

वार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को दिल्ली में नई लैंडफिल साइट के निर्माण को लेकर नगर निगम और भाजपा पर निशाना साधा। आप नेताओं ने दावा किया कि नगर निगम दिल्ली में 16 नई लैंडफिल साइट का निर्माण करना चाहता है। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिल्ली नगर निगम और भाजपा पर हमला बोला है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में 16 और कूड़े के पहाड़ हो गए तो राजधानी कूड़े का शहर बन जाएगी। हम दिल्ली को तिरंगों का शहर, झीलों का शहर, बगीचों का शहर, अच्छे स्कूलों का शहर, अच्छे अस्पतालों का शहर बना रहे हैं। ये लोग दिल्ली को कूड़े का शहर बनाने पर तुले हुए हैं। हर कॉलोनी में कूड़े का पहाड़ बनाना चाहते हैं।

वहीं, आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा ने कूड़े के पहाड़ों को ताजमहल-कुतुबमीनार की तरह पुलिस-सीआरपीएफ की सुरक्षा दी हुई है। ताकि कोई बिना टिकट न घुस जाए और छेड़छाड़ न कर दे। आप विधायक एवं निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने डीडीए, डीसिब, जल बोर्ड और केंद्र सरकार से कूड़े के पहाड़ों के लिए जमीन की मांग की है।



ओखला लैंडफिल साइट पर गुरुवार को भाजपा शासित नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते आप नेता-कार्यकर्ता। • हिन्दुस्तान

ओखला लैंडफिल साइट पर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में कूड़ा-कूड़ा अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को आप नेता ओखला लैंडफिल साइट पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। हालांकि आप विधायक सौरभ भारद्वाज पुलिस बैरिकेड के चलते साइट पर नहीं चढ़ पाए।

मौके पर मौजूद विधायक सहीराम ने कहा कि घनी आबादी के पास कूड़े

वे पांच साल से झूठ बोल रहे : सौरभ भारद्वाज

विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज की मुहिम का नाम 'भाजपा का चमत्कार देखो कूड़े का पहाड़ देखो' है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद पांच साल से झूठ बोल रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए। कूड़े के पहाड़ पर पुलिस का पहरा लगा रखा है कि लोग वीडियो-फोटो न ले सकें।

का पहाड़ बनने से लोग कैसर, दमा, टीबी से पीड़ित हो गए हैं। विधायक करतार सिंह ने भी भाजपा पर आरोप

लगाए। वहीं, तुगलकाबाद विधायक सहीराम पहलवान ने कहा कि कूड़े के पहाड़ हटाने में भाजपा नाकाम है।

पलटवार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में नई लैंडफिल साइट बनाने के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा की ओर से उपमुख्यमंत्री को चुनौती दी गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि उपमुख्यमंत्री नगर निगम पर लगाए झूठे आरोप को साबित करें या माफी मांगें।

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि यह बेहद दुखद है कि उपमुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद मनीष सिंसोदिया ने राजनीतिक बौखलाहट में दिल्ली नगर निगम पर 16 नई लैंडफिल साइट बनाने का झूठा आरोप लगाया है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मनीष सिंसोदिया के शराब घोटाले के नित नए स्टिंग सबूत सामने आ रहे हैं। एक नया स्टिंग सबूत गुरुवार को भी सामने आया जिससे सिंसोदिया ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है। शराब घोटाले के सबूत से ध्यान भटकाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने नगर निगम पर मनगढ़ंत आरोप लगाया है।

नई लैंडफिल साइट की योजना नहीं : निगम

दिल्ली नगर निगम का कहना है कि राजधानी में 16 स्थानों पर नई सैनिटरी लैंडफिल साइट स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। इस तरह के दोवों में सच्चाई नहीं है। नगर निगम मौजूदा कूड़े के पहाड़ों को ही खत्म करने में जुटा हुआ है। नई लैंडफिल साइट बनाने की कोई तैयारी नहीं की गई है।

15 मीटर तक कम कर दी ऊंचाई

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा तीनों लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम करने के लिए ट्रामल मशीनें स्थापित की हैं। कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई दस से 15 मीटर तक कम कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा अप्रैल 2022 तक निगम में सत्ता में थी लेकिन न तब कोई नया लैंडफिल साइट बनाने का प्रस्ताव था, न ही आज अधिकारियों के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022

NAME OF NEWSPAPERS-----

-----DATED-----

Instead of clearing garbage, MCD plans to set up 16 landfills: Sisodia

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Deputy chief minister Manish Sisodia on Thursday claimed that Municipal Corporation of Delhi was planning to set up 16 new landfill sites to dump garbage collected from across the city.

Terming it a "dangerous plan", Sisodia said the move would put the lives of Delhiites in danger and severely affect their health.

"Instead of clearing the three mountains of garbage, the BJP-led MCD is now coming up with new landfill sites, which will add to the woes of residents. This dangerous plan of BJP will put the life of Delhiites in danger and impact their health severely. BJP wants to convert Delhi into a garbage city," said Sisodia. He added, "If these landfill sites come up according to BJP's plan, similar mountains of garbage will be visible all over Delhi."

AAP has launched a month-long campaign to expose BJP for its failure to keep the city clean. Party functionaries on Wednesday invited people to Ghazipur landfill site to show them the mountain of garbage and took them to Okhla on Thursday.



Rajesh Mehta

SISODIA SAYS

If these landfill sites come up, similar mountains of garbage will be visible all over Delhi. Other cities also generate huge amounts of garbage, but they have well-planned strategies to manage it

Alleging that the BJP-led MCD failed terribly in managing the landfill sites, Sisodia said Delhi was not the only metropolitan city dealing with the problem of waste. "Other metropolitans also generate huge amounts of garbage, but they have well-planned strategies in place to manage it. The BJP-led MCD ne-

ver paid attention to clearing the landfill sites," he added.

Calling MCD's plan disastrous, Sisodia claimed the Kejriwal government had a "robust plan" to deal with the issue. "People should give a chance to Arvind Kejriwal in MCD too. He has a complete plan to eliminate the mountains of garbage," he said.

AAP MLAs Atishi, Durgesh Pathak and Dilip Pandey also held separate press conferences and alleged that MCD was setting up 16 new landfill sites. AAP chief spokesperson and Greater Kailash MLA Saurabh Bharadwaj took a group of residents to the Okhla landfill site where police had barricaded the area and didn't allow anyone to enter the area.

"The BJP-controlled Delhi Police converted the mountain of trash into a fortress to stop people. We are bringing Delhiites to the landfill sites to see the reality. We are showing everyone what a colossal failure BJP has been in managing the sanitation and garbage situation," said Bharadwaj.

Pandey alleged that people living near the Ghazipur landfill site were being diagnosed with skin and lung cancer. "The groundwater has arsenic in excessive amounts. A third-party audit should be conducted in this matter," he added.

Pathak alleged that MCD had so far spent Rs 1,200 crore in the name of reducing the three garbage mountains and was now asking various government agencies, including DDA, DUSIB and Delhi Jal Board, to set up more landfills.

एयर क्वालिटी इंडेक्स पीएम 2.5

दिल्ली	
आज का अनुमान	18 अच्छा
बृहस्पतिवार	20 अच्छा

दिल्ली विश्वविद्यालय

आज का अनुमान	27 अच्छा
बृहस्पतिवार	30 अच्छा

आयानगर

आज का अनुमान	38 अच्छा
बृहस्पतिवार	27 अच्छा

गुरुग्राम

आज का अनुमान	27 अच्छा
बृहस्पतिवार	33 अच्छा

0	60	अच्छा
---	----	-------

61	90	सामान्य
----	----	---------

91	120	खराब
----	-----	------

121	160	बहुत खराब
-----	-----	-----------

161 से आगे		खतरनाक
------------	--	--------

पार्टिकुलेट मैटर (प्रदूषक तत्व पीएम 2.5) माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है। सामान्य स्तर 90 निर्धारित है।

कूड़े के 16 नए पहाड़ बनाना चाह रही भाजपा

नई लैंडफिल साइटों के निर्माण पर बोले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी में नई लैंडफिल साइटों के निर्माण को लेकर बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली नगर निगम और भाजपा पर निशाना साधा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आप के तीन नेताओं ने दावा किया कि निगम और मनीष सिसोदिया • भाजपा राजधानी में 16 नई लैंडफिल साइट बनवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर निगम और भाजपा पर निशाना साधा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कूड़े के 16 और पहाड़ बन गए तो राजधानी कूड़े का शहर बन जाएगी। हम राजधानी को तिरंगों, झीलों और बगीचों का शहर, अच्छे स्कूलों और अस्पतालों का

कहा- 15 वर्ष में भाजपा की नाकामी को दिखाते हैं राजधानी में कूड़े के मौजूदा पहाड़, दिल्ली वालों का जीना हो गया है मुश्किल

शहर बना रहे हैं। ये कूड़े का शहर बनाने पर तुले हैं।

सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में जहां-जहां कूड़े के पहाड़ हैं, वहां लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर भाजपा की यह साजिश सफल हुई तो कूड़े के 16 नए पहाड़ राजधानी को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कूड़े के इन पहाड़ों को खत्म करने का पूरा प्लान है।

इस बार दिल्लीवासी शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए निगम में भी आप को मौका दे। सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में कूड़े के मौजूदा तीन पहाड़ 15 वर्ष

में भाजपा की नाकामी को दिखाते हैं। भाजपा ने इनके प्रबंधन के लिए तो कुछ नहीं किया, अब 16 और स्थानों को नर्क बनाकर दिल्लीवासियों का जीना दुश्वार करना चाहती है।

आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा ने कूड़े के पहाड़ों को ताजमहल-कुतुबमीनार की सुरक्षा दी हुई है। आप विधायक एवं नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने डीडीए, डूबिब, जल बोर्ड और केंद्र सरकार से कूड़े के पहाड़ों के लिए जमीन मांगी है। उन्होंने कहा कि आप आरडब्ल्यूए, सिविल सोसायटी, एनजीओ और जनता की मदद से भाजपा की साजिश को सफल नहीं होने देगी। पार्टी नेता एवं विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि भाजपा केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, दिल्ली वालों की सीरियल किलर भी बन रही है।

झूठा है 16 लैंडफिल बनाने का दावा: निगम

जास, नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने उस दावे का खंडन किया, जिसमें 16 स्थानों पर लैंडफिल (कूड़े के पहाड़) बनाने की बात कही गई थी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावे पर बयान जारी कर नगर निगम ने कहा कि वह इन आरोपों को नकारता है और स्पष्ट भी करता है कि नई लैंडफिल साइट स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, जबकि वर्तमान लैंडफिल ओखला, भलस्वा और गाजीपुर को समतल करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई 10-15 मीटर तक कम कर ली गई है। निगम के प्रेस एवं सूचना निदेशालय ने कहा कि हम लैंडफिल साइटों को समतल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसे लेकर भ्रम न फैलाया जाए।

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 16 सितंबर 2022

दिल्ली में कूड़े के 16 और पहाड़ खड़े करने की तैयारी में बीजेपी: सिसोदिया

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

एमसीडी चुनावों की आहट मिलते ही दिल्ली में एक बार फिर कूड़े पर राजनीति तेज हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि दिल्ली में कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म करने की बजाय बीजेपी दिल्ली में 16 जगहों पर कूड़े के ऐसे नए पहाड़ और खड़े करने की योजना बना रही है। अगर ये प्लान लागू हो जाता है, तो दिल्ली की जनता की सेहत के लिए ये खतरनाक साबित होगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पूरा प्लान है कि कैसे कूड़े के इन तीनों पहाड़ों को खत्म किया जा सकता है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी जहां कूड़े के तीन पहाड़ हैं, उनके आसपास रह रहे लोगों को हर वक्त बदबू झेलनी पड़ती है। इन कूड़े के पहाड़ों पर आग लगती है और धुआं लोगों के घरों में घुसता रहता है।

आप विधायक दुर्गेश पाठक और आतिशी ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। दुर्गेश पाठक ने दावा किया कि दिल्ली में 16



प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया

किया दावा

■ भलस्वा, नरेला, बवाना, रानीखेड़ा, सुल्तानपुर डबवास समेत अन्य कॉलोनियों में 16 नई सैनिटरी लैंडफिल साइट्स बनाने के लिए जमीन छोट ली गई है

■ प्लान लागू हुआ तो दिल्ली की जनता की सेहत के लिए ये खतरनाक साबित होगा

नए कूड़े के पहाड़ खड़े करने के लिए भाजपा ने डीडीए, डूबिब, जल बोर्ड और केंद्र सरकार से जमीन की मांग की है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस प्लान का पूरजोर तरीके से विरोध करेगी और पूरी दिल्ली में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।

बीजेपी की चुनौती, आरोप साबित करें

विस, नई दिल्ली: बीजेपी द्वारा दिल्ली में कूड़े के 16 नए पहाड़ और बनाने की तैयारी करने के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दावे के जवाब में बीजेपी ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा है कि या तो वह निगम पर लगाए गए अपने इस आरोप को साबित करें या माफी मांगें। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सिसोदिया ने 16 नए लैंडफिल साइट बनाने का आरोप लगाया है, जो पूरी तरह झूठा आरोप है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में नित नए सिंग ऑपरेशन और सबूत सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नया सिंग गुरुवार को सामने आया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ही नहीं, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है। उसी बौखलाहट के चलते और शराब घोटाले के सिंग से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उप-मुख्यमंत्री ने यह पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- DELHI THE HINDU ---DATED---
FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022

BJP-run MCD planning to create 16 more landfills in Delhi: Dy. CM

No such plans, instead corporation working to flatten existing landfills, says BJP

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Thursday alleged that the Municipal Corporation of Delhi (MCD) is planning to create 16 new landfills in the city.

The BJP, in response, said AAP had stooped to a "new low" by "levelling a false allegation" against the MCD.

Mr. Sisodia said the BJP-run MCD has given three mountains of garbage to Delhi and, instead of working to get rid of them, the corporation was now coming up with plans for new landfill sites across the city.

'Lives at risk'

"This plan of the BJP will put the lives of Delhiites in danger. The BJP, which is on its way out of the MCD, wants to convert Delhi into a garbage city," Mr. Sisodia said.

"Chief Minister Arvind



This plan of the BJP will put the lives of Delhiites in danger. The BJP, which is on its way out of the MCD, wants to convert Delhi into a garbage city

MANISH SISODIA
Deputy Chief Minister

Kejriwal has a plan to eliminate the mountains of garbage in Delhi. To make Delhi clean and beautiful, people must give AAP a chance in the MCD as well," he added.

Responding to the allegations, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said that there were no proposals to set up new landfill sites by the erstwhile BJP-run corporations - North, South and East.

He added that the recently unified MCD also has "no plan" of setting up new sani-

tary landfill sites in the city. He also said that the civic body has instead been working towards flattening the three existing landfill sites at Bhalswa, Okhla, and Ghazipur.

A senior MCD official familiar with developments said the civic body has explored options of acquiring land for landfill sites before the corporation's trifurcation.

"Around 2008, when the MCD was yet to be trifurcated, we got some land from

the Uttar Pradesh government. This was for the purpose of dumping waste since the Ghazipur landfill was already full," the senior MCD official said.

He added, "We also paid an advance of around ₹5 lakh. But due to resistance from the locals in the area, the government refused to hand over the land to us."

Exploring options

The official said, "Even now nobody in Delhi and NCR wants to give land to MCD for a landfill. But the corporation is still exploring its options."

AAP leader Durgesh Pathak alleged that the MCD had asked for land from DDA, DUSIB and Delhi Jal Board to set up new landfills.

"If the BJP succeeds, there will not be any area left in city without a landfill," Mr. Pathak added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

millenniumpost

पंजाब केसरी
DELHI

FRIDAY, 16 SEPTEMBER, 2022 | NEW DELHI

Centre may allow compensatory afforestation in neighbouring states for land diverted in Delhi

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Union environment ministry may allow compensatory afforestation (CA) for all developmental projects undertaken in Delhi in neighbouring states in view of the scarcity of land in the capital, sources have said.

A source in the Environment Ministry said they have taken cognisance of the Delhi Development Authority's (DDA) letter which said all green areas in the city have saturated and there is a severe shortage of land to raise compensatory afforestation for the upcoming developmental projects.

"This is a policy issue. We have taken note of it. There is indeed a shortage of land in Delhi. We are going to take up the matter in a meeting of the Forest Appraisal Committee of the ministry. The request is likely to be accepted," the source said.

Citing a recent order of

the National Green Tribunal (NGT), noted environmentalist Prof C R Babu said the forest clearance is subject to the requirement of afforestation within 10 km from the place where the trees were felled.

"Compensatory afforestation for forest land diverted in Delhi should be done in the city itself. The authorities should utilise the small open spaces in institutional areas, schools and colleges for this purpose," he said.

Faiyaz Khudsar, the scientist-in-charge at the Yamuna Biodiversity Park in north Delhi, said if at all CA needs to be done outside Delhi, efforts should be made to restore the degraded land on the periphery of the capital using an ecological approach which would also alleviate the impact of dust storms.

A senior DDA official said it has denied several requests by user agencies, including the National Highway Authority of India and Railways, to provide

land for compensatory afforestation considering the shortage.

In March, the DDA wrote to the Union Environment Ministry, requesting it to allow compensatory afforestation for all projects undertaken in Delhi in neighbouring states in view of the scarcity of land in the capital.

In its letter, the DDA cited para 2.3 (v) of the chapter 2 of the Handbook of Forest Conservation Act which says: "In exceptional cases where non-forest land/degraded forest land, as the case may be, for CA is not available in the same state/Union territory in which the diversion of forest land is proposed, land for CA can be identified in any other state/UT, preferably in a neighbouring state/UT."

"It is proposed that para 2.3(v) of the guidelines issued by the ministry may in general be relaxed for Delhi and CA may be allowed in neighbouring states," the DDA's letter read.

विकास के लिए काटे गये वृक्षों के वनीकरण की मंजूरी जल्द

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में जमीन की कमी को देखते हुए दिल्ली में चल रही सभी विकास परियोजनाओं के वास्ते काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों में वनीकरण की मंजूरी दे सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पर्यावरण मंत्रालय में एक सूत्र ने बताया कि उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक पत्र पर संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि शहर में सभी हरित क्षेत्र भर गए हैं और आगामी विकास परियोजनाओं के लिए प्रतिपूर्ति वनीकरण के वास्ते जमीन की भारी कमी है। सूत्र ने कहा, "यह एक नीतिगत मुद्दा है। हमने इस पर संज्ञान लिया है। निश्चित तौर पर दिल्ली में जमीन की कमी है। हम मंत्रालय की वन मूल्यांकन समिति की बैठक में इस मामले को उठाने जा रहे हैं। इस अनुरोध



केंद्रीय
पर्यावरण
मंत्रालय एक्शन
में

को स्वीकार किए जाने की संभावना है।" राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक हालिया आदेश का जिक्र करते हुए जानेमाने पर्यावरणविद्

प्रोफेसर सी आर बाबू ने कहा कि वनों की कटाई पर उस जगह से 10 किलोमीटर के दायरे में वनरोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "दिल्ली में परिवर्तित वन भूमि की प्रतिपूर्ति के लिए वनरोपण शहर में ही होना चाहिए। अधिकारियों को संस्थागत क्षेत्रों, स्कूलों और कॉलेजों में छोटे खुले स्थानों का उपयोग इस उद्देश्य से करना चाहिए।"

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE HINDU DELHI
FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022

-----DATED-----

Compensatory afforestation in other States likely

Union Environment Ministry has taken cognisance of DDA's letter seeking permission, says official

MUNEEF KHAN
NEW DELHI

The Union Environment Ministry is likely to allow compensatory afforestation (CA) for development projects executed in the Capital in neighbouring States due to shortage of land in Delhi, according to a senior Ministry official.

The official said the Ministry has taken cognisance of the Delhi Development Authority's (DDA) request for the same but refused to elaborate further. The issue of shortage in land for CA was flagged by the DDA in two letters to the Ministry in March this year and in May 2021.

Senior DDA officials, who are familiar with the development, said they have not received any communication on the Ministry's likely move to allow CA in the neighbouring States.



Facing land shortage, the DDA has not been able to attend to requests from service agencies executing development projects in the Capital. ■ FILE PHOTO

On September 11, *The Hindu* had reported that the DDA continued to face land shortage due to which it had not been able to attend to requests from service agencies executing development projects in the Capital. The most recent request, according to a senior DDA official, was for around 25 hectares for CA to the Indian Railways.

In the March 30 letter to the Environment Ministry, DDA's vice-chairman Manish Gupta had sought relaxation in the guidelines issued under the Forest Conservation Act, 1980, for CA to be allowed on degraded forest land in neighbouring States for projects implemented by the Centre and public sector undertakings.

In 2021, the DDA had provided 119.76 hectares to various service-providing agencies for CA, according to data provided by the senior DDA official.

Compensatory Afforestation, according to the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980, has to be carried out for diversion of forest land or deemed forest land for non-forest purposes, while the purpose of CA is to compensate for the loss of "land by land" and loss of "trees by trees".

'Exclusive relaxation'

Earlier, the senior official in the Environment Ministry had told *The Hindu* that the DDA was not facing any land shortage for CA and it was only looking for an "exclusive relaxation" by proposing CA on "double degraded forest land".

According to paragraph 2.3(i) of chapter 2 of the Act, CA has to be raised on suitable non-forest land, which is equal to the area proposed for diversion, at the cost to be paid by the user agency.

Simultaneously, paragraph 2.3 (iii) states that in cases where non-forest land is available but to a lesser extent, CA can be carried out on degraded land which is twice the extent of the forest area that is being diverted.

The Ministry official had earlier said the DDA was pushing for a relaxation to carry out CA on "double degraded forest land, which we will not allow".

He had said that the urban body had over 5,000 hectares on the Yamuna floodplains, which remains encroached upon and "the DDA was not acting on this".